

न्यायालय जिला कलक्टर गंगापूर सिटी  
पीठासीन अधिकारी डॉ० गौरव सैनी

अपील संख्या 13/23

तारीख रज्जू- 12/09/23

1. टीकाराम पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी ककराला तहसील वागनवासा ।
2. जीतराम पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी ककराला तहसील वागनवासा ।

-अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार वागनवासा ।

-रेस्पॉडेन्ट

निर्णय

दिनांक 09/09/24

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वागनवासा द्वारा गिराल संख्या 76/2020 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम ककराला के आराजी ख०नं० 1831 रकबा 0.78 है० किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से वेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया है। जिसकी तामिल किसी भी व्यक्ति पर नहीं हुई है, इसलिए सूचना न होने के उपरान्त भी यह आरोपित आदेश पारित करने में अदालत मातहत द्वारा कानूनी भूल की है। उक्त प्रकरण को सिद्ध करने हेतु पटवारी हल्का के बयान आवश्यक थे, लेकिन अदालत मातहत द्वारा ना तो पटवारी हल्का के ना ही गिरदावर के बयान लिये गये है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने दरतावेजों की सूची में अंकित फर्द गौका रिपोर्ट ग्राम ककराला दिनांक 18.01.2021 की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ख०नं० 1831 में हम कॉलोनी वारियों के पट्टे सन् 1975 व 1982 में जारी किये गये है, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में कॉलोनी का अंकन नहीं होने से भूमि आज भी गै०मु०चरागाह दर्ज है, साथ ही अधिवक्ता



*[Signature]*  
7/9/24

जिला कलक्टर  
गंगापूर सिटी (राज०)

अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

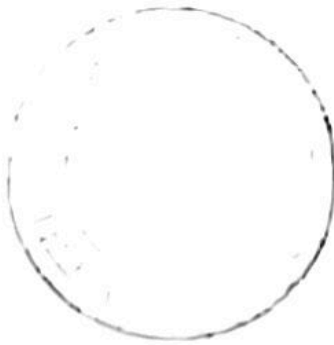
विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेशेकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सन्नत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे।

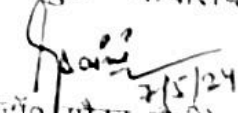
दोनों पक्षों की बहस सुनने, उस पर गहन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सन्नत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया तथा अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 14.10.2020 पर स्वयं अपीलार्थी सं० 1 के हस्ताक्षर अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि सन् 1975 व 1982 में पट्टे जारी किये गये थे। लेकिन वकील अपीलार्थी द्वारा वाद आराजीयात के पट्टे की प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है। वर्तमान में उक्त भूमि की किरम चरागाह है तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद आराजीयात चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किये हैं।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अपील अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवदेना के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा भिसल संख्या 76/2020 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ० गौरव सेनी)  
जिला कलक्टर  
मंगलपुर सिटी (उ०)  
2024/05/07